

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या:-153/2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक:- 23/10/2023
निर्णय दिनांक:- 29/08/2025

अनवान

1. तेजपालसिंह चुण्डावत पुत्र शंकरसिंह चुण्डावत जाति राजपुत निवासी लालजी का खेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

---प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द जरिये प्रतिनिधि राज्य सरकार।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी की ग्राम लालजी का खेडा, पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खातेदारी कब्जे की कृषि भूमियां स्थित है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 58 आराजी संख्या 102, 73, 85 कुल किता 03 कुल क्षेत्रफल 1.7500 हैक्टेयर स्थित है। यह भूमि प्रार्थी खातेदारी व कब्जे की है इस भूमि से आगे विपक्षी संख्या 01 की भूमि आराजी संख्या 72 किस्म गै.मु.चट्टान स्थित है जिससे होकर प्रार्थी अपनी कृषि आराजियात में प्रवेश कर सकता है व पगडण्डी रूपी रास्ते से अपनी भूमि में प्रार्थी आ जा रहा है तथा इसी आराजी से प्रार्थी कृषि उपकरण, हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर कल्टी इत्यादि का आवागमन विपक्षी संख्या 01 की भूमि में



होकर किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 01 की भूमि के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उद्देश्य प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन कर उसका उपभोग-उपयोग करना है प्रार्थी की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी उपरोक्त भूमि के आगे की तरफ विपक्षी की आराजी संख्या 72 स्थित है जो मुख्य सड़क ग्राम लालजी का खेडा जाने वाली से लगी हुई है जिसके विपक्षी संख्या 01 मालिक है उक्त आराजी संख्या 72 में से चाहा गया है जिससे प्रार्थी अपनी आराजियात में प्रवेश कर सकता है। प्रार्थी एवं उसके परिवारजन वर्षों से इस रास्ते से आवागमन कर रहे हैं एवं वाहन, ट्रेक्टर, ट्रौली, मशीनरी, मवेशी ला ले जा रहे हैं तथा लम्बे समय से खुले तौर पर निरन्तर निर्विघ्न विपक्षी संख्या 01 की जानकारी में प्रार्थी एवं उनके पूर्वाधिकारियों का इसी रास्ते से आवागमन करते रहे हैं। विपक्षी संख्या 01 की उक्त वर्णित भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्त चाहा गया है जिससे प्रार्थी अपने वाहन, मशीनरी, उपकरण इत्यादि ले जा सकते हैं प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन के अधिकार बाधित होकर प्रार्थी अपनी भूमि आराजी संख्या 73 में आने जाने व वाहन ट्रेक्टर, ट्रौली, कल्ट्री, कृषि उपकरण एवं मवेशी आदि लाने ले जाने से वंचित हो जाएंगे। इस आराजी नम्बर 72 के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में जाने का नहीं है। विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 72 में से प्रार्थी की आराजी संख्या 73 में आवागमन (रास्ता) 12 फीट चौड़ा को धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रास्ते के रूप में कायम किया जाना आवश्यक है जिसके लिए यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कायम करने के लिए जो भी मुआवजा राशि न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है प्रार्थी अदा करने के लिए तैयार है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण की भूमि



आराजी संख्या 72 में से आवागमन का रास्ता जिसका विवरण प्रार्थना-पत्र की कलम संख्या 02 में दिया गया है उस 12 फीट चौड़े रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे एवं रास्ते की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करवाने की कृपा करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक पारड़ी एवं पटवारी हल्का पारड़ी की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात में जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है एवं परिवारी जहां रास्ता चाहता है वहां पर मौके पर मकान बने हुए है जहां से रास्ता दर्ज किया जाना संभव नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि पर जाने हेतु एवं भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु ट्रैक्टर, ट्रौली व अन्य मशीनरी ले जाने के लिए लिए रास्ते की नितान्त आवश्यकता है एवं 12 फीट रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने भू-अभिलेख निरीक्षक पारड़ी एवं पटवारी हल्का पारड़ी की जांच रिपोर्ट की ताईद की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-ए में प्रतिपादित है कि:- [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an



existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]



तेजपालसिंह बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्या:- 153/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:-29/08/2025

पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा सिर्फ सुविधा के लिए नया रास्ता चाहा गया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अ.सहायक कलेक्टर A.S.)
सहायक कलेक्टर, जिला राजसमन्द
जिला राजसमन्द